is aware that the said land was again allotted as a compensation to the person concerned.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Most of the land is used for development activities and some land has been given to three parties because there are special reasons. If the hon. Member wants it, I can give the same.

SHRI MANORANJAN BHAKTA: This is a very serious matter. In the north-eastern region, you know the local people are agitating on many grounds. When we find that the people coming from outside are allotted land even after 10 years in Andamans for construction purposes and the old inhabitants are deprived of their ligitimate and ancestral property, it will be a case of heart burning. I would again ask a pinpointed question whether the hon. Minister would like to re-examine the whole issue and review it in the larger interest of the country.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: There is no question of reviewing the matter because the land was resumed because it was not used for the purpose for which it was allotted by the Government. Most of the land, as I said, is used for development activities, such as, bus terminus, schools, electricity offices, transport workshops, PWD worskhops, market, etc. About the remaining land which is allotted to three parties, 160 Sq. M. have been allotted to one Shri Ashiq Ali in lieu of his having surrendered a major portion of his house-site located at Port Blair in favour of the Government for widening an important road passing along his house-site; 320 Sq. M. have been allotted to one Shri Mashooq Ali who has a small industrial unit registered with the Director of Industries for the purpose of setting up a bakery—he is a descendant of an old inhabitant settled in the Islands prior to 1942.

The third piece was given to the Andamans & Nicobar Islands Co-operative Cafeteria which is a Co-operative body registered under the Andamans & Nicobar Islands Cooperative Societies Act, 1978. The land has been allotted to this society for the construction of a cafeteria as well as a lodging house to be run on Co-operative basis, which is intended to provide cheap and clean accommodation for the transit passengers. These are allotments made in the public interest.

SHRI MANORANJAN BHAKTA: My question was whether you will provide compensation at least.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I would like to reply to that part. The question of compensation does not arise because the terms and conditions of allotment under the Act are such.

छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाना

*44. श्री भीखा भाई :
कुमारी कमला कुमारी :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है,

(ख) वे क्षेत्र कौन-कौन से हैं जिन पर इस योजना में अधिक ध्यान दिए जाने की व्यवस्था है; और

(ग) योजना के अंत तक राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि की प्रतिशतता का लक्ष्य क्या है ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) सरकार ने यह निर्णय किया है कि नई पंचवर्षीय योजना वर्तमान वर्ष के अंत तक तैयार कर दी जाएगी जो 1980-81 से 1984-85 तक की अवधि के लिए होगी, और जिससे नई सरकार की प्राथमिकताएं अभिव्यक्त होंगी । अस्थायी रूप में, योजना आयोग ने राष्ट्रीय आय की वृद्धि की 5 प्रतिशत वार्षिक

दर को नई योजना के लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया है । इसके साथ ही, यह योजना तैयार करते समय और अधिक उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने की संभावना का भी जांच की जाएगी ।

नई योजना के ब्यौरे तैयार करने के लिए अभ्यास किए जा रहे है । इस अवस्था मे क्षेत्र-वार ब्यौरे बनाना संभव नही है ।

श्री भोखा भाई अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न के प्रथम भाग मे पूछा है कि कितने समय मे योजना का प्रारूप तैयार होगा, मन्त्री जी ने समय तो बताया परन्तु उत्तर में यह नही बताया गया है कि योजना को तैयार करने में इतनी देर क्यो हुई है ।

"The sectors which are proposed to be given more attention in the above Plan."

मै इसमे जानना चाहता हू क्या सोशल सर्विसेज मे, खास तौर पर ट्राइबल वेलफेयर को प्राथमिकता दी जायगी और इसके लिए क्या आउटले होगा ?

"The tragetted percentage increase in the national income by the end of the Plan."

इसमे जो रेट बताया गया है वह 5 परसेंट बताया गया है ।

"5 per cent annual rate of growth of national income .

मै जानना चाहता हू कि 5 परसेंट रेट आफ ग्रोथ बताया गया है और उससे अधिक कहा तक हो सकता है, उसके लिए प्रयत्न किया जायेगा लेकिन इसका इफेक्ट पर-कैपिटा इनकम पर क्या होगा ? मान लीजिए सन् 1970 को बेस ईयर माना जाए तो क्या स्थिति आयेगी और प्लान का आकार क्या होगा ? ये प्रश्न बडे महत्वपूर्ण है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी · माननीय सदस्य ने प्रथम तो यह जानना चाहा है कि योजना तैयार करने मे इतनी देरी क्यों हो रही है । श्रीमन्, आप सहमत होंगे कि नई सरकार के पद ग्रहण के बाद जो कार्य शुरू किए गए, नई सरकार की नीतियां और कार्यक्रमो के अधीन योजना के प्रारूप को तैयार करने में, उसमें थोड़ा समय अवश्य लगेगा । यह हमारी विनम्र चेष्टा होगी कि हम अधिक से अधिक शीघ्रता कर अपने निष्कर्षों और परिणामों तक पहुंच सकें । इस सम्बन्ध में विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श करना आवश्यक होता है । साथ ही साथ राज्य सरकारों का सहयोग भी अपेक्षित होता है, उनसे परामर्श लेना होता है । हमारा प्रयास होगा कि इस वर्ष के अन्त तक योजना के प्रारूप को अंतिम रूप दे दे ताकि अगले वर्ष के प्रारम्भ में राष्ट्रीय विकास परिषद उस प्रारूप पर विचार कर सके ।

जहा तक ट्राइबल वेलफेयर का प्रश्न है, आदिवासियो के विकास के लिए जो परियोजनाये है उनको आवश्यक प्राथमिकता देना हमारे दलीय कार्यक्रमो का मुख्य अग रहा है । मै विद्वान सदस्य को आश्वस्त करना चाहूगा कि ट्राइबल वेलफेयर आदिवासियो के विकास के प्रश्न को अवश्य औचित्यपूर्ण प्राथमिकता दी जायेगी ।

जहा तक माननीय सदस्य ने प्रति व्यक्ति आमदनी मे वृद्धि का उल्लेख किया है, श्रीमन्, आप जानते है कि विश्व की आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार से चिन्तनीय है और उसका प्रभाव हमारी आर्थिक व्यवस्था पर भी पड़ रहा है । मूल्य वृद्धि एक विषम चक्र है परन्तु हमारा प्रयास है कि जहा मूल्य वृद्धि रुके, उसमे संतुलन आय, वहा हमारा यह प्रयास भी होगा कि इस संतुलन प्राप्ति के साथ साथ हमारी योजना का आकार-प्रकार इस प्रकार का हो कि हमारी राष्ट्रीय आय बढे और राष्ट्रीय आय बढने के परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति आय अपने आप ही वृद्धिमान होगी, माननीय सदस्य इस बात से सहमत होगे और प्रति व्यक्ति आय कितनी बढेगी, उसके बारे मे विविध अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन उसका इस समय निश्चित अनुमान लगाना, विद्वान सदस्य इस बात से सहमत होगे, जरा व्यावहारिकता से दूर होगा ।

कुमारी कमला कुमारी . अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महादय क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना मे सिर्फ आदिवासियो के विकास का ही प्रश्न है या हरिजनो के विकास का भी प्रश्न है ? दूसरी बात मै मंत्री महोदय से यह जानना चाहूगी कि इस योजना की आधारशिला किन-किन बातो पर निर्भर करती है, जो कि इस योजना के अन्तर्गत आयेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी . श्रीमन्, मै विद्वान सदस्या को आश्वस्त करना चाहूगा कि मेरा अभिप्राय कभी भी, जो योजना मे हरिजन वर्गों के लिए प्राथमिकताये है उनकी, अवमानना करना नही है । मै तो केवल राजस्थान के विद्वान सदस्य के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा था । उन्होने केवल ट्राइबल वेलफेयर का प्रश्न पूछा था, तो मेरे लिए यह औचित्यपूर्ण नही था कि मै उसके साथ जो प्रश्न उन्होने नही पूछा, उसका उत्तर भी जोड़ दू ।

डा० कर्ण सिंह · अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह बताया कि यह जो नई योजना बन रही है, वह 1980–81

से लेकर 1984–85 तक चलेगी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना को सम्पूर्ण करने के लिए इस वर्ष के अन्त तक का समय तो लगेगा ही । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब इस नई योजना को बनाने में एक वर्ष का समय लगेगा ही तो फिर इस योजना को 1981–82 से लेकर और 1985-86 तक क्यों नही चलाया जाए, क्योंकि एक वर्ष तो जब तक योजना तैयार होगी, उसमें समाप्त हो जाएगा । हर पांच वर्ष बाद चुनाव होते हैं और नई सरकार आती है, उसको कुछ समय मिलना चाहिए कि उसके जो विचार है, जो नीतियां है, उनका प्रतिबिम्ब उस योजना में हो, तो इस बार यदि यह 1981–82 से आरम्भ करके 1985–86 तक चले तो इससे दो लाभ होंगे--एक तो यह कि एक वर्ष खराब नहीं होगा और दूसरे इस योजना का लाभ भविष्य में देश को होगा । इस सुझाव के ऊपर मंत्री महोदय जवाब दें ।

MR. SPEAKER: That is a suggestion you can consider it.

SHRI R. L. BHATIA: The Minister has stated in his statement that it will take quite some time before the plan is finalised. But he has also made a categorical statement that there will be a five per cent growth rate. When the Plan is not ready, how can he make a categoriacl statement that there will be a five per cent growth rate in it? I would like to know from the hon. Minister what is the bosis on which he has assumed that there will be a five per cent growth rate.

MR. SPEAKER: Shrimati Susheela Gopalan.

SHRIMATI SUSHEELA GOPLAN: May I know from the hon. Prime Minister whether the Chief Ministers will have an opportunity to discuss the Plan in detail in the National Development Council before it is finalised?

SHRI N. D. TIWARI: The Chief Ministers are hon. Members of the National Development Council, and I am sure that we shall have the benefit of their advice.

SHRI R. L. BHATIA: Sir, he has not replied to my question. I put a question...

अध्यक्ष महोदय: मैंने समझा कि आपने आपस में समझ लिया होगा ।

SHRI R. L. BHATIA: The Minister says that the Plan is not yet ready and it will take some time, but at the same time he makes a categorical statement that there will be a five per cent growth rate. I am asking him as to what is the basis on which he has assumed this five per cent growth rate.

MR. SPEAKER: He did not say that.

श्री मूल चंद डागा: पिछली सरकार ने पंच वर्षीय योजना का जो प्रारूप बनाया था, चाहे वह रोलिंग प्लान हो या जो भी हो, उस में और आज जो आप नया प्लान बना रहे हैं उस में, क्या मतभेद होंगे, क्या सैद्धांतिक अन्तर होगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी: विद्वान सदस्य को ज्ञात होगा कि पिछली सरकार ने योजना के दो प्रारूप बनाये थे--एक मार्च, 1978 में और दूसरा दिसम्बर, 1979 में और वे प्रारूप पिछली सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को घोषित करते थे । जो उन्होंने दिसम्बर, 1979 में अन्तरिम प्रारूप बनाया था उस में स्वयं इस बात का उल्लेख था कि जिस प्रकार से मूल्यों की अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है और तेल-संकट का प्रभाव पड़ रहा है, इस कारण...

MR. SPEAKER: Please make it short.

श्री नारायण दत्त तिवारी: मैं आप की अनुज्ञा चाहूंगा, श्रीमन्, क्योंकि प्रश्न महत्वपूर्ण है । उत्तर यह है कि हमारा नया प्रारूप नई सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को परिलक्षित करेगा इसलिये उस में बुनियादी मतभेद स्वभाविक रूप से रहेगा ।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Call a meeting of the Consultative Committee. That will be the best answer.

PROF. MADHU DANDAVATE: While preparing the draft Sixth Plan, the most important aspect will be the question of priorities. Soon the Budget will be coming and there will be allocations made to various sectors

of our economy and in the light of that, if the question of priorities is not settled as early as possible, in that case, the whole economy is likely to be upset and the direction will be wrong. In view of this, will you try to cut short the period and expedite the framing of the Sixth Plan rather than waiting for one more year or so?

MR. SPEAKER: He said that he is waiting for only six months.

SHRI N. D. TIWARI: We will try to expedite the formulation of the Plan.

श्री प्रताप भानु शर्मा माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय मंत्री जी इस बात को बतलाने की कृपा करेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना में देश की बढ़ती हुई बेरोजगार नौजवान सदस्यों की संख्या को दृष्टि में रखकर तथा उस समस्या को हल करने के लिये क्या कोई विशेष प्रारूप तैयार किया गया है ? यदि तैयार किया गया है तो उसका विवरण देने की कृपा करें ?

श्री नारायण दत्त तिवारी श्रीमन्, मैं विद्वान सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बेरोजगारी के प्रश्न पर योजना में आवश्यक प्राथमिकता अवश्य दी जायगी । मैंने स्वयं प्लानिंग कमीशन में अपने साथी सदस्यों से कहा है कि इसके लिये विशेष वर्किंग ग्रुप बनाया जाये । वर्किंग ग्रुप निर्मित किया जा रहा है जो विभिन्न बेरोजगारी को दूर करने की योजनाओं को समन्वित करेगा ।

Shortage of Newsprint

*45. SHRI V. S. VIJAYA RAGHAVAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether there is an acute shortage of newsprint in the country;

(b) the total installed capacity and the percentage of utilisation at present; and

(c) measures taken to ease the shortage?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHANNA CHARANJIT): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Although certain communications have been received from some newspapers referring to difficulties in getting newsprint, there is no general shortage of newsprint in the country as adequate quantity of newsprint is being imported to supplement the domestic production.

(b) The installed capacity of National Newsprint & Paper Mills, which is the only unit producing newsprint in the country is 67,500 tonnes. However, due to imbalance between the pulping and paper manufacturing capacity, operational problems and shortage of power, the capacity utilization over the last few years has been about 70-75 per cent.

(c) In order to meet the gap between domestic production and demand, adequate quantity of newsprint is being imported. Government have issued the following letters of intent for setting up various newsprint projects in the country:-

	Capacity
1. M/s. Century Pulp	20,000 tonnes/year
2. Shri B. D. Somani	50,000 tonnes/year
3. M/s. Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited	83 000 tonnes/year

Apart from the above M/s. Hindustan Paper Corporation are setting up a newsprint project with a capacity of 80,000 tonnes per annum in Kerala State which is likely to go into production in 1981-82.

M/s. Mysore Paper Mills, Bhadravati are putting up a newsprint project for a capacity of 75,000 tonnes per